(b) if not, when it is likely to be finally settled; and

(c) the steps taken for the expeditious settlement of the dispute?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) No, Sir.

(b) and (c). All efforts are being made for an early settlement of the dispute. Two discussions have been held with the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra and these discussions are expected to be continued to arrive at a satisfactory settlement.

केरल को बिजली की सप्लाई

*79. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मोहम्मद कोया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार द्वारा मद्रास परिषण लाइन से केरल को जो बिजली सप्लाई की जायेगी, उसकी दर दुगनी कर दी जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो वास्तविक दर क्या होगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो उद्योगपति तथा कृषक परिवर्तित दर के अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनको बिजली की सप्लाई कम कर दी जायेगी; और

(घ) परिवर्तित दर का औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ). केरल की पन-बिजली परियोजनाओं के जलाशयों में निम्न जल स्तर के कारण वहां हुई बिजली की कमी को दूर करने के लिये केरल राज्य बिजली बोर्ड ने मैसूर से मद्रास ग्रिड के जरिये 3 से 4 लाख यूनिट बिजली प्रति दिन लेने का प्रबन्ध किया है । मद्रास राज्य बिजली बोर्ड, जो कि मैसूर को इस ऊर्जा के प्रति यूनिट के लिये 9 पैसे देता है, पारेषण के लिये 3 पैसे प्रति यूनिट खर्च लेता है और इस प्रकार केरल को ऊर्जा की लागत 12 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है । बिजली की इस अतिरिक्त सप्लाई के केरल राज्य बिजली बोर्ड को इस समर्थ बना दिया है कि उस ने उद्योगों के लिये बिजली में 75 प्रतिशत कटौती की बजाए 50 प्रतिशत की कटौती की, यदि अतिरिक्त बिजली की सप्लाई न होती तो 75 प्रतिशत कटौती अनिवार्य हो जाती । केरल राज्य बिजली बोर्ड को मैसूर से लाई जाने वाली बिजली के परिणामस्वरूप टैरिफ को दुहराना नहीं पड़ा है । किन्तु, बिजली के इस आयात पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये राज्य बोर्ड ने उद्योगों पर लागू बिजली टैरिफ पर 100 प्रतिशत अधिभार लगाने का निर्णय किया है । जिन उद्योगों ने इस अधिभार को स्वीकार कर लिया है उन के लिये अब बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है और जिन थोड़े से उद्योगों ने इस को मानने से इन्कार किया है, उन के लिये 75 प्रतिशत की कटौती की गई है । किसानों के लिये न ही तो कोई बिजली की कटौती की गई है और न ही उन पर कोई अधिभार लगाया गया है ।

राज्य में बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में कुछ कमी हो जाने की सम्भावना है ।

Aid from Czechoslovakia

*80. **Shri Shree Narayan Das:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Shri M. L. Dwivedi: